

Mr. Deputy-Speaker: That will come up later when the House has to grant the permission.

Mr. Siddhanti.

19.28 hrs.

**MOTION RE: SITUATION ON
INDIA-PAKISTAN BORDERS**

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (इज्जर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ :—

“कि यह सभा भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर स्थिति के बारे में 1 अगस्त, 1966 को प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है।”

हमारे रक्षा मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उस की ओर मैं एक, दो मिनट के लिए उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने सार में यह कहा है :—

“I can only give broad indications.”

दूसरा :

“Since the period of Indo-Pakistan conflict in September, 1965, Pakistan has been making all-out efforts to increase its armed strength.”

Then:

“New fixed defences are being constructed and others improved. Ordnance factories are being set up and expanded.”

“Pakistan has also obtained assistance of one or two other countries for the supply of arms and equipment.”

इस पर मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे सीमाओं की रक्षा के लिए सब से आवश्यक पहली बाण यह है कि सीमाओं को सुदृढ़ किया जाये। अब सीमाएं सुदृढ़ कैसे हो सकती हैं? अपनी सीमाओं से जितनी भी लगती हुई शत्रु दशों की सीमाएं हैं उतनी

दूर तक अपनी सीमाओं पर हमारी भारतीय सेना से जो सैनिक जवान सेवा निवृत्त हो चके हैं उन को वहाँ सीमाओं पर भूमि दी जाये और उन को बसाया जाये।

जितने लोग वहाँ पर रहते हैं उन को हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाये, गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग दी जाये और सारे साधन उन के पास रहें ताकि वह हमारे देश पर शत्रु के पहले आक्रमण को रोकने में समर्थ हो सकें।

साथ ही जो वहाँ के रहने वाले सैनिक हैं तथा दूसरे रहने वाले हैं उन को आईडेंटिटी कार्ड्स दिये जायें जिस में कि पता चल सके वह हमारे देश के रहने वाले नागरिक हैं, और दूसरे घुसपैठियों आदि की पहिचान हो सके। इस लिये सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए जो मेरा सब से पहला सुझाव है वह यह है कि सीमा के साथ जो हमारे देश का भाग लगता है वहाँ के रहने वालों को पूरी तरह से हथियारों के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाये।

दूसरा सुझाव यह है कि जासूसों को गहरी खोज की जाये, चाहे वह भीतर के हों या बाहर के हों। काश्मीर में हम ने देखा कि वहाँ पर जो घुसपैठिये बाहर से आये उन को काश्मीर के अन्दर रहने वाले कुछ लोगों ने सहयोग दिया जासूसों के लिए केन्द्रीय सरकार इतना सुदृढ़ प्रबन्ध करे जिस से कि उन की जांच की जा सके। जब वह पकड़े जायें तब उन को अदालतों में पेश करने की आवश्यकता न हो, बल्कि मिटिलटरी के कोर्ट मार्शल नियमों के अनुसार उन को कठोर दंड दिया जाये जिस में वह दुबारा फिर न उभार सकें।

[श्री जगदेशव सिंह सिद्धांती]

इसी तरह से जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जहाँ पर भी बाहर के आने वाले मार्ग हैं उन पर हमारे सैनिक पिकेट बढ़े सुदृढ़ होने चाहिये। और उन के पास मारी-मामग्री होनी चाहिये जिस से कि आक्रमण में जो जोर का आक्रमण शत्रु का होना है उसको रोकने में वे समर्थ हो सकें। बाद में उनको जल्दी से पूरी महायता पहुँचाई जाये।

इसी तरह से जो हमारे रेलवे हैं, चाहे रेलवे पुल हों या रेलवे हॉट, उनकी रक्षा का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये जिससे कोई भीतरी शत्रु ऐसी कार्यवाही न कर सके जो बाहरी आक्रमण होने पर हमारी सेना के काम में रुकावट डाले। सड़कों की रक्षा भी इसी तरह से ठीक ढंग से होनी चाहिये ताकि वहाँ पर मिलिटरी का जितना भी हामान हो उसको, राशन और अम्बुनिशन आदि को, ट्रांसपोर्ट के द्वारा वहाँ पर पहुँचाने में पूरी मुविधा हो। इस प्रकार के कार्य करके सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री कपूर सिंह : (लुधियाना) : भीतरी शत्रु कौन है ?

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : भीतरी शत्रु वह होता है जो बाहरी शत्रु को सहायता देता है : जसा कि एक अभी कांग्रेस पार्टी में पकड़ा गया है। यह मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्र हित में कहना चाहता हूँ।

लद्दाख और काश्मीर में चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ हमारा झगड़ा है। चीन चालाक ज्यादा है और पाकिस्तान जलिम ज्यादा है। दोनों का ध्यान रख कर ही ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे दोनों का मकाबला ठीक ढंग से हो सके।

पहाड़ी क्षेत्र में भूटान, सिक्किम, असम वगैरह प्रदेश आते हैं जहाँ हमारी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिये। नागा और मिजो इन दोनों के पाँछे जो अनेकतत्व हों, मेरा यह विचार है कि सरकार को उनके साथ कोई बातचीत नहीं करनी चाहिये, बल्कि कठोर पग उठा कर जो देशद्रोही पाये जायें उनका दमन कर दिया जाये।

जहाँ तक पूर्वी पाकिस्तान का संबंध है, चूँकि पश्चिमी पाकिस्तान यह समझता है कि वहाँ पर वह बहुत सैनिक सहायता नहीं पहुँचा सकता इसलिये उसने वहाँ पर एक तरह से चीन को बुलाया हुआ है कि तुम यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दो और प्रशिक्षण केन्द्र खोलो हथियार दो। बहुत सी जगहों पर उनके लोग आये हुए हैं। भारत सरकार को और माननीय प्रतिरक्षा मंत्री जी को इसका पूरा ध्यान रखना है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ध्यान रक्खा भी होगा परन्तु फिर भी हमें इस बात पर बल देना है कि यदि किसी कारण से कोई भूल रह जाये तो उसको निकाल कर स्थिति का पूरी तरह ध्यान रखें। पूर्वी पाकिस्तान सीमा से जिस प्रकार दूसरा शत्रु हमारे अन्दर गड़बड़ी करवा सकता है, हमारा यह कर्तव्य है कि शत्रु को नीचा दिखाने के लिये साम, दाम, दण्ड, भेद, जिस तरह से भी हो सके हमको अपना काम करना चाहिये।

अभी जैसे कल परसों बात आई थी जिनको इमरजेंसी कमिशन दिया गया था उनमें कुछ छंटनी हो रही है। मेरा मुझाब है कि इस समय उनको सेना से छंटनी न की जाये। जिन लोगों को सरकार राष्ट्र सेवा के नाते से लेना चाहे उनके ऊपर तो इतनी आपत्ति नहीं की जा सकती, लेकिन आपत्ति इस पर होती है कि जब शत्रु सामने गरज रहा है, प्रति दिन उनको मूचनाएँ आती हैं और अमरीका, रूस या जितनी शीविदे शक्तियाँ हैं वह हमसे कुछ कहती हैं और उनसे कुछ कहती हैं, तब उन लोगोंकी छंटनी की जा रही है।

इन बातों पर ध्यान रख कर हमारी जितनी प्रकार की सेनाएँ हैं, खाली स्थल सेना ही नहीं उन को नये से नये अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया जाये ।

जब हम को यह मालूम है कि अमरीका से भी पाकिस्तान को हथियार आये हैं कुछ सीधे आते हैं, कुछ तुर्की और ईरान हो कर अप्रत्यक्ष रूप से पहुँच रहे हैं, उधर चीन भी दे रहा है, इन बातों का ध्यान हृदय में रख कर हमें अपने हथियारों का प्रबन्ध करना चाहिए जो भी आर्डिनेंस फैक्ट्री हैं उन के अन्दर ज्यादा से ज्यादा काम हम को करवाना चाहिए जितना कि अब तक नहीं हुआ है । पिछले दिनों हम लोग देखने गये थे । यह सन्तोष का विषय था कि कुछ काम हो रहा है, लेकिन उस से ही हम को सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये, बल्कि ज्यादा प्रगति करनी चाहिये । इस के लिये मेरा एक मुझाव भी है । जो भी अपने निजी उद्योग हैं, उन से भी सरकार को सहायता लेनी चाहिये और उन में सैनिक सामान बनवाना चाहिये, कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ । हाँ, यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि किसी प्रकार की कोई आपत्ति-जनक बात उन में न आये । इस लिये निजी उद्योगों के अन्दर एक उच्च मिलिटरी का अधि-कारी वहाँ रहना चाहिये जो पूरी तौर से इस के ऊपर निगरानी रखे और प्रत्येक निजी उद्योग के ऊपर सरकार का पूरा नियन्त्रण रहे ।

नवीनतम हथियार जो हैं, जो कि हमारे यहाँ अब तक नहीं बने हैं, उन को बाहर से मंगाने का भी हम को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिस से वह हमें मिलते रहें । कोई ऐसी बात न हो कि हमें न मिलें और शत्रु को मिलते रहें मैं समझता हूँ कि हमारे ध्यान में यह जरूर है, लेकिन मैं माननीय प्रतिरक्षा मंत्री से निवेदन करूँगा कि न

वह अमरीका के झांसे में रहें और न रूस के झांसे में रहें, बल्कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिये अमरीका से जो मिल सके उसे लें और रूस से जो मिल सके वह लें । अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में उन को खुद अपने ऊपर ही भरोसा रखना चाहिये ।

अणुशक्ति के बारे में हमारे राष्ट्रीय नेताओं को न मालूम क्या सनक सवार हो रही है कि जब आज संसार में अणुशक्ति का बाहुल्य है, और यह बढ़ती जा रही है तब वह यह नारा लगाते हैं कि हम अणु बम नहीं बनायेंगे, अणुशक्ति मिलिटरी के काम में नहीं लायेंगे । मैं कहता हूँ कि वह लोग देश को गहरी नींद में मुला रहे हैं, पराधीनता की बेड़ियाँ में फँसा देना चाहते हैं । इसे कारण हमें अणु अस्त्रों और अणु शस्त्रों के निर्माण के ऊपर भी पूरी शक्ति लगानी चाहिये । अगर सामने अणुशक्ति वाला है और हमारे हाथ में छोटी बन्दूकें 1857 वाली हैं, तोड़े हैं, तो क्या तोड़ा और अणुशक्ति का मुकाबला हो सकता है ? हम को हर प्रकार के हथियारों का प्रयोग करना चाहिये और सब को उन की पूरी शिक्षा देनी चाहिये । जितने हमारे प्रौढ़ लोग हैं उन्हें भी अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा दी जाये ।

मैंने आज आप के सामने मोटे रूप से यह बातें रखी हैं । आज हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस पर सामान्य रूप से ध्यान दें । यदि हम ने इधर ध्यान नहीं दिया और दूसरी बातों में फँसे रहे, तो यह हमारी बड़ी भूल होगी ।

इस सम्बन्ध में और भी बातें आ जाती हैं, कहीं खाल समस्या है, कहीं कोई और समस्या है, लेकिन मैं आप के द्वारा अपने युवा और मार्शल मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर शरीर में प्राण हैं तो शरीर बचा रहेगा, अगर शरीर में प्राण नहीं हैं तो सब चीजें नष्ट हो जायेंगी । इसलिये सब चीजों की रक्षा के लिये जो कुछ भी बनता

[श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती]

है, उस की रक्षा के लिये अपनी सेना को सुदृढ़ कीजिये और उन में जो सैनिक हैं उन को प्रोत्साहित कीजिये। जो सुविधायें हैं वे सब सैनिकों को दी जानी चाहियें। यह देखा जाना चाहिये के उनमें घर वालों के ऊपर, उनके बाल बच्चों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट न आने पाए। मेरे पास सैनिक लोग प्रायः आते रहते हैं। क्योंकि मैं भी भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं उन की बातें प्रतिरक्षा मंत्री को लिखता रहता हूँ और वह मुझे उत्तर भी देते रहते हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि वह उन पर विचार भी करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि और भी अधिक सहानुभूति उनकी ओर बरतनी चाहिये। एक सैनिक की मोर्चे पर मृत्यु हो गई। उसके घर वाले मेरे पास आए। उसकी धर्म पत्नी की पैशन हो गई है जो कि बहुत अच्छी बात है। उस बेचारी देवी की दो लड़कियां हैं। अब उस पैशन से उसका ही गुजारा हो सकता है। उसके माता पिता हैं जोकि वृद्ध हैं। उनके खाने कमाने का कोई प्रबन्ध नहीं है। पांच भाइयों में कुल ग्यारह कच्चे बीघे जमीन है। अब आप देखें कि कैसे उनका गुजारा हो सकता है। मैं सुझाव दूंगा कि जितने सौल्जर बोर्ड हैं उन बोर्डों से फेहरिस्त मांगी जाए कि कौन से ऐसे सैनिक हैं जिन के घरों में किसी बात की कोई कमी है और जब यह पता चल जाए तो उस कमी को पूरा करने की व्यवस्था की जाए। इससे वे लोग प्रोत्साहित होंगे और बराबर सैनिक सेवा करने के लिये तैयार रहेंगे।

● मैं आपको अपने क्षेत्र की बात बताता हूँ। मेरे अपने क्षेत्र में घर-घर में सैनिक बैठे हुए हैं। कोई कमी वहां सैनिकों की नहीं है। इस बात के सूत्र भी मिल चुके हैं कि उन्होंने बहुत वीरता से पिछली लड़ाई में काम किया है। टिथलाव के मोर्चे से ले कर गाडरा के मोर्चे तक हमारे वीर सैनिकों ने जितनी बहादुरी से काम किया उसको आप जानते

हैं। वे आगे और भी अधिक बहादुरी से काम करेंगे। लेकिन उनकी सुख-सुविधाओं की तरफ आपको देखना चाहिये। अगर कोई सैनिक नाकारा हो गया है तो उस सैनिक को सिविल के अन्दर भी काम देने की व्यवस्था होनी चाहिये। जितने अधिक से अधिक सैनिकों को सिविल में खपाया जा सकता है, खणने की कोशिश की जानी चाहिये। बाकी तो फिर भी भुगत सकेंगे ज्यों-त्यों लेकिन सबसे पहले सैनिकों का प्रश्न हमारे सामने रहना चाहिये। यही हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। लडाख की चोटियों पर, गिलगित के अन्दर नेफा के अन्दर और सभी जगह पर ये बैठे हुए हैं और लड़ रहे हैं बरफ में, गर्मी में, सर्दी में। अगर यहां पर पंखा ठीक से नहीं चलता है तो शोर मच जाता है। लेकिन उनको न गर्मी की और न सर्दी की कोई परवाह है। उनके पास अगर कम हथियार हैं तो उसको भी उनको परवाह नहीं है। वे अपनी पूरी सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से सीमाओं के ऊपर खड़े हुए हैं। हमारी सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि ऐसे वीर सैनिकों के लिए जिस सामान की उनको आवश्यकता है, उसको भेजने की व्यवस्था की जाए। आपको मालूम ही है कि चुशल के मोर्चे की क्या अवस्था हो गई थी। एक बहादुर मेजर जनरल वहां पहुंचा। उसने चीनियों को न केवल वहां से खदेड़ा बल्कि टिड्डियों की तरह से उनको मसल कर रख दिया। हमारे वीर सैनिकों ने चुशल के मोर्चे की रक्षा की। एक रेजिमेंट जिसमें डेढ़ सौ बहादुर थे उन्होंने उसकी रक्षा की। वे हमारे रिवाड़ी के बहादुर थे। वे अहीर रेजीमेंट के थे। उन्होंने उस बहादुर जनरल के साथ चुशल के मोर्चे को बचाया। जो मार्शल रेसिस हैं वे तमाम की तमाम प्राणों की आहुति देकर बराबर देश की रक्षा करती हैं। पहले भी मैंने कहा था और आज भी प्रतिरक्षा मंत्री जी से मैं कहता हूँ कि आप ट्रेनिंग सब को दें। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जनता को प्रशिक्षण दें, कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन परम्परा से, जो सदा से लड़ते आए हैं

पहाड़ों पर और मैदानों में और जिन्होंने सदा से शत्रुओं से लोहा लिया है, विदेशी आक्रमकों से लोहा लिया है और जिनके घरों में आज भी 1857 से पहले के शस्त्रास्त्र दीवारों के अन्दर चुने हुए हैं, ऐसे बहादुरों को आप आगे लायें। वे हमारे देश की रक्षा करेंगे। जिन्होंने परम्परा से लड़ाई नहीं की, जिन्होंने मोर्चा नहीं देखा, इस प्रकार के लोग जब आ जाते हैं तो वे अस्पतालों में चले जाते हैं। ऐसे लोगों पर आप भरोसा न करें।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भेरे सुझाव हैं उनके ऊपर प्रतिरक्षा मंत्री जी अच्छी तरह से विचार करें और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि हम सम्पूर्ण राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने में सफल होंगे।

Mr. Deputy-Speaker : Motion moved:

"That this House takes note of the statement made by the Minister of Defence on the 1st August, 1966 regarding situation on Indo-Pakistan borders."

Two hours is the time allotted. We should close by 2-30. So, Members will please take ten minutes each.

श्री भागवत श्यामराज (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया है वह है हमारे प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने एक अगस्त और आठ अगस्त को जो बयान सदन के सम्मुख दिये हैं, उन पर विचार किया जाए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रतिरक्षा मंत्री जी के ये दोनों बयान बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन बयानों से हमें यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान ताशकंद 1516(ai)LSD-7.

भावना की किस प्रकार से हत्या करके सैनिक साज सामान और हथियार बढ़ा रहा है। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री जी ने हमें बताया है कि पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने का हर प्रयास कर रहा है। उसके सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। उसने अपने 5 डिविज़नों को बढ़ाकर ग्यारह डिविज़न कर लिया है। उसकी आर्मंड कोर में भी वृद्धि हो रही है, ऐसा प्रतिरक्षा मंत्री जी ने कहा है। पिछले युद्ध में जबकि उसकी आर्मंड कोर को बहुत हानि उठानी पड़ी थी, आज उसने उसकी पूर्ति कर ली है। जहां तक टैंकों का सम्बन्ध है, उसे चीन से दो सौ टैंक मिल चुके हैं और, और टैंक लेने का वह इंतजाम कर रहा है। इसके साथ ही साथ नए पी० ओ० के० डिविज़न उसने खड़े कर लिए हैं, अर्थात् पाकिस्तान अधिकृत जम्मू काश्मीर में न केवल उसने डिविज़न की संख्या को बढ़ाया है बल्कि तीस हजार जन शक्ति को भी और उसने संगठित किया है। इन तमाम चीजों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें विस्तार से उनके जो स्टेटमेंट हैं उनमें दी गई हैं।

बहस का मुख्य आधार आज यह है कि हम देखें कि संसार की कौन-कौन सी शक्तियां हैं जो पाकिस्तान की सहायता कर रही हैं। अगर चीन पाकिस्तान की सहायता कर रहा है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चीन हमारा दुश्मन है। वह हमारे देश के एक बहुत बड़े भाग को दबोच बैठा है। हमें उससे भी लड़ाई लड़नी है। इसलिए इससे हमें जरा भी आश्चर्य नहीं होता है कि चीन ने पाकिस्तान को दो सौ टैंक दिये हैं, उसने पाकिस्तान को मिग 19 और मिग 21 दिये हैं। पाकिस्तान के पास आज पांच और ज्यादा पहले के मुकाबले में एयर स्क्वैड्रन हो गए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि वे तमाम देश जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान

[श्री भागवत झा आजाद]

श्रीर हिन्दुस्तान के बीच में तटस्थ हैं वे किस प्रकार से किस की सहायता करते हैं। सब से बड़ी आश्चर्य की स्थिति जो सामने आई है वह यह है कि कनाडा ने जो सेबर जेट्स पश्चिमी जर्मनी को दिये और पश्चिमी जर्मनी ने ईरान को दिये वही सेबर जेट्स ईरान के जरिये पाकिस्तान में आ गए हैं। सब से बड़ा दुख हमको इंग्लैंड की जनता से है वहाँ की सरकार से है। कामनवैल्य का यह हमारा मित्र किस प्रकार का है कि जो हमारी पीठ में छुरा घोंपता आया है? इसको अब यहां श्रीर अधिक बताने की आवश्यकता नहीं रह गई है। पिछले युद्ध में जबकि पाकिस्तान आक्रमक था तब उसने कहा कि हमने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है कामनवैल्य के एक बहुत बड़े पार्टनर इंग्लैंड ने कहा कि हम आक्रमक हैं और हमने पाकिस्तान पर चढ़ाई की है। आज भी सब से बड़ी बात जो इंग्लैंड कह रहा है उसको आप देखें। हिन्दुस्तान की सरकार और प्रतिरक्षा मंत्री को आज देखना यह है कि इंग्लैंड इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि अमरीका ने जो बैं लगाया है पाकिस्तान को हथियार देने पर, उसको वह कहता है कि हटा लिया जाए। इंग्लैंड यह कहता है कि हमने हिन्दुस्तान को अस्त्र दिये हैं और अमरीका ने पाकिस्तान को दिये हैं। चूँकि हम अब अपने अस्त्रों पर से रोक हटा रहे हैं इसलिए अमरीका को भी पाकिस्तान को अस्त्र देने पर उसने जो रोक लगा रखी है, उसको हटा लेना चाहिये। सब से बड़ी और भयंकर बात जो मैं प्रतिरक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ यह है कि क्या यह सच नहीं है कि इंग्लैंड पूरी कोशिश कर रहा है कि अमरीका ने जो रोक लगा रखी है पाकिस्तान को हथियार देने पर, उसको अमरीका हटाले ?

इसके साथ-साथ एक दूसरी बात और है। अमरीका ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को नान-

लीयल वैपंज देंगे। यह सबको मालूम है कि उसने यह कहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहाँ तक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है नान-लीयल वैपंज का अर्थ होता है मोटर गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, नान-लीयल वैपंज का मतलब क्या यह नहीं होता है जो कि पैंटगोन करेगा? क्या उसने यह नहीं कहा है कि इसका अधिकार हम सुरक्षित रखते हैं, हम इसकी व्याख्या करेंगे? अर्थात् अमरीका पाकिस्तान को नान-लीयल वैपंज देने के सम्बन्ध में बराबर यह अधिकार अपने पास रखता है कि नान-लीयल वैपंज के नाम पर लीयल वैपंज उस को दे दे। मैं प्रतिरक्षा मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने अमरीकी सरकार से इस बात को पूछा है कि उस के उच्चाधिकारी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नान-लीयल वैपंज का मतलब है पैंटगोन जो कहे वही रहेगा या नान-लीयल वैपंज का मतलब वह है जो कि इंग्लिश डिक्शनरी में मिलता है या जो डिक्सेस की डिक्शनरी में मिलता है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इंग्लैंड की हरकतों को हम सब जानते हैं। अब स्वयं इंग्लैंड में इस बात का जोर है कि कामनवैल्य नाम का यह अजनबी, कामनवैल्य नाम का यह बेकार और यूजलेस आर्गनाइजेशन टूट जाए। और इंग्लैंड जैसे विद्रोही और देशघाती, अर्थात् कामनवैल्य-घाती जिसने हिन्दुस्तान की पीठ में छुरा मारा और जो आज भी प्रयत्न कर रहा है अमेरिका के पास कि उस पर से बैं हटा ले, उस को तो हम समझते हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ जब कनाडा के प्रधान मंत्री पियर्सन ने स्टेटमेंट दिया। हम कनाडा को कामनवैल्य के उन मेम्बरों में मानते थे जो सोबर बंग से देखते हैं, जिनका अपना देखने का तरीका एक अनवा-यस्ड और बैलेंस्ड है, लेकिन जब इस पार्लियामेंट में इस बात पर जोर दिया गया कि कनाडा ने वह बम-बर्षक विमान सेबर जेट्स जो वेस्ट जर्मनी को दिया, ईरान से पाकिस्तान को आये,

त कैनडा के प्रधान मंत्र पियर्सन ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा पाकिस्तान तो कामनवेल्थ में रहता है, झुंसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों इस बात की शिकायत हिन्दुस्तान में हो रही है, आखिर उन पर कोई बैन तो है नहीं उन के पास भेजने का। यः पियर्सन का स्टेटमेंट है। मैं उसको लाया तो था लेकिन दुर्भाग्यवश कोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पियर्सन साहब ने यह आश्चर्य प्रकट किया कि हिन्दुस्तान को इस बात पर क्यों आश्चर्य हो रहा है कि बम-बर्षक विमान कॅनाडा से बैस्ट जर्मनी, वहा से ईरान और ईरान से पाकिस्तान को पहुंचे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कामनवेल्थ का दोस्त है और कोई उन पर बैन नहीं है देने पर। तो आज मैं यह देखता हूँ कि मरीका की यह हालत, इंग्लैंड कामनवेल्थ का मित्र उसकी यह हालत और साथ-साथ कॅनाडा जिस को हम कामनवेल्थ के सोबर मॅम्बर में से समझते थे, उस के प्रधान मंत्री पियर्सन ने यह स्टेटमेंट देकर के इस देश की भावनाओं को बड़ा आघात पहुंचाया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है अर्थात् उन के कहने का मतलब यह है कि आज पाकिस्तान को अगर बम वर्षक दिये जायें तो उस में कॅनाडा को कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी भाषा के बहुत से अर्थ हुआ करते हैं लेकिन जो स्टेटमेंट पियर्सन साहब ने दिये उस के अर्थ बड़े स्पष्ट हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान की हम यह नहीं चाहते कि अपने देश की योजनाओं को तोड़कर अपने देश की जनता के मुख की रोटी छीन कर के हम उस के लिये औजार बनायें। हम नहीं चाहते कि हम अपने देश में भूख और बेकारी से लड़ने के बजाय अस्त्र बनायें लेकिन जब सीमाओं पर खतरा

है और जब सीमाओं पर खतरा करने वाले पाकिस्तान को चीन अपनी सहायता कर ही रहा है, हमें कोई शिकायत नहीं है उससे लेकिन उसको सहायता करने के सबसे बड़े अपराधी आज वह मित्र-राष्ट्र हैं, वह पश्चिमी जर्मनी, वह ईरान, वह कॅनाडा, वह अमरीका जो बार-बार इस बात की दोहाई दे रहे हैं कि आपस में मेल हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पर जोर दूँ इस स्टेटमेंट के संबंध में और वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वह यह है कि इस देश के रुपये का अवमूल्यन हुआ यह तो एक आर्थिक समस्या है, मैं इस बात पर जोर नहीं देता, लेकिन मैं एक बात के लिये अपनी सरकार को आगाह करता हूँ और वह यह है कि फिर अमरीका वर्ल्ड बैंक के जरिये या और किसी देश के जरिये दबाव डालने वाला है कि हम अपने देश की सुरक्षा की तैयारियों के खर्च में कमी करें। मैं जानता हूँ कि यह दबाव या सुझाव वह तो सुझाव कहेंगे दबाव क्यों कहेंगे वह तो सलाह देते हैं सिर्फ दबाव नहीं डालते हैं तो यह बात आने वाली है फिर अमरीका वर्ल्ड बैंक के जरिये या वर्ल्ड बैंक क्या है, अमरीका वर्ल्ड बैंक कहा जाय, अमरीका के हाथ में युनाइटेड नेशन्स पोलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है और वर्ल्ड बैंक आर्थिक इंस्ट्रूमेंट है, तो उस के जरिये से आज फिर इस देश पर दबाव डाला जा रहा है। प्रतिरक्षा मंत्री जी जो इस देश की भावनाओं का जो इस देश के डिटरमिनेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह याद रखें कि अगर ऐसा कोई सुझाव जिसको हम दबाव समझते हैं, आपके सामने लाया गया और जिस का रेफरेंस अपने भाषण में श्री रवीन्द्र वर्मा ने दिया है कि वर्ल्ड बैंक इस देश पर दबाव डालने वाला है या डाल रहा है कि इस देश की प्रतिरक्षा की तैयारियों में कमी की जाय, तो हम इस बहस में इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं,

[श्री भागवत झा आजाद]

हम जानते हैं कि वह हमारे पश्चिम के मित्र कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, लेकिन हमको सारी सहायता अभी पूर्वी यूरोप के देशों से मिल रही है। मैं नहीं जानता कि कौन देश कितना दे रहा है, यूगोस्लोविया से क्या मिल रहा है, रूस से क्या मिल रहा है लेकिन वह जानना चाहता हूँ कि अपने देश की सैनिक तैयारियों में वह हमें वतलायें कि किस अर्थ में अमेरीका से हमें सहायता मिल रही है, वेस्ट जर्मनी से मिल रही है या और देशों से मिल रही है? आप अगर इस देश की अपनी रक्षा की तैयारियों में हवाई जाहज मिले हैं, टैंक मिले हैं, मिजाइल्स मिले हैं तो वह उन पूर्वी देशों से मिले हैं, जिन देशों ने हमें पहले भी सहायता की और आज भी कर रहे हैं। इसलिये इस बात को समझ कर के इस पर बयान दिया जाय।

मैं एक और प्रमुख बात की और इशारा करूँ। मैं जानता हूँ सरकार की ऐटम बम के संबंध में क्या नीति है। उस नीति पर अभी मैं नहीं जाता। उस के ऊपर अबसर आयेगा विदेश नीति के संबंध में। लेकिन मैं प्रतिरक्षा मंत्री से जानना चाहता हूँ कि मान लीजिये आपने वह फैसला कर लिया कि हम ऐटम बम नहीं बनायेंगे, आप चाहते हैं कि संसार में शांति हो, आप याद रखिये कि कार्यों की शांति कोई शान्ति नहीं होती, कमजोरों की शांति कोई शान्ति नहीं होती। शांति मजबूतों की होती है। शांति वह करवा सकते हैं जो मजबूत हों। जब-जब युद्ध लड़े गये हैं युद्ध का विनाश करने के लिये तो वह जिन के पास तैयारियाँ रही हैं, उन के द्वारा वह लड़ाइयाँ लड़ी गई है। हम अपने रक्षा मंत्री से जानना चाहते हैं कि अगर ऐटम बम की तैयारी नहीं, तो आपकी मिजाइल्स

की क्या तैयारी है? हम जानना चाहते हैं कि आप ने जिस महत्वपूर्ण प्रश्न को डिफेंस एक्सपर्ट्स को सौंपा था चाइना के ऐटमिक ब्लास्ट के बाद उस संबंध में आप क्या कर रहे हैं? आपका मिजाइल प्रोग्राम क्या है?

दूसरी बात यह है कि आज पैना में कन्वेंशनल वेपन्स का प्रोग्राम ऐटमिक पावर से भी होने लगा है। अर्थात् ऐसे भी कन्वेंशनल वेपन्स हैं जिनको चलाने के लिये ऐटमिक पावर का प्रयोग हो रहा है, तो क्या आप यह चाहते हैं कि हमने ऐटम बम नहीं बनाया, हमने मिजाइल्स के कार्यक्रम को नहीं बनाया, हम ऐटम शक्ति का प्रयोग उन कन्वेंशनल अस्त्रों के लिये भी नहीं करेंगे जिनका प्रयोग आज अन्य देशों में हो रहा है। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रतिरक्षा मंत्री जी इन दो चार पांच प्रश्नों पर जो मैंने उठायें हैं, विचार करेंगे और यह आश्वस्त करेंगे कि इस संबंध में सरकार उचित कार्यवाही कर रही है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (विजनीर):
उपाध्यक्ष जी, प्रतिरक्षा की जिन समस्याओं पर आज हम विचार कर रहे हैं वह परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जब चोट खाया हुआ सांप फिर फुफकार कर हमारे दरवाजे पर आ कर खड़ा हुआ है। प्रतिरक्षा मंत्री यह दोनों वक्तव्य जो अभी कुछ समय पहले उन्होंने सदन में दिये थे इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि सीमाओं पर लड़ाई के बादलों का रंग बढ़ी तेजी से गहरा होता जा रहा है। नहीं कहा जा सकता कि यह युद्ध रुपी राक्षस जो पीछे कुछ समय से हमारा द्वार बार बार खटखटाता रहा है किस समय हमें फिर विवश करे मोर्चों पर आने के लिये।

चीन और पाकिस्तान दोनों के गठबन्धन से जो परिस्थितियाँ हमारी सीमाओं पर उत्पन्न हुई हैं और जो स्थिति भारत के पूर्वी भाग में धीरे-धीरे विषम होती चली जा रही है उसी का प्रमाण कुछ दिन पूर्व मिजो पहाड़ियों में देखने को मिला। मिजो पहाड़ियों के अतिरिक्त भी नागाओं के प्रतिक्षण के पीछे और अब कुछ दिनों से सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जो क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिस में गारो पहाड़ियों के भी कुछ लोग सम्मिलित हैं, उस में पाकिस्तान और चीन का पूरी तरह हाथ है। चीन ने नेफा में मंगोल शकल के बहुत से लोगों को घुसपैठियों के रूप में भेजा है और बदकिसमती से सालों से चिल्लाते रहने के बाद भी आज आसाम के अंदर 27 लाख पाकिस्तानी आ कर बैठ गये हैं जिनको भारत सरकार निकालने में असमर्थ है। अभी पीछे आसाम में जो दो-चार स्थानों पर उपद्रव हुए उस में स्पष्ट रूप से इन पाकिस्तानियों का हाथ था। इधर पूर्वी पाकिस्तान की सैनिक कमान पूरी तरह चीनी अधिकारियों के हाथ में आ गई है। वह पूर्वी पाकिस्तान में टूनिंग दे रहे हैं और उस के अतिरिक्त जहाँ सब से बड़ा चीन का उद्देश्य पाकिस्तान के साथ मिल कर दिखाई पड़ रहा है वह है चुम्बी बैली पर धीरे-धीरे दबाव बढ़ाना। हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति आये कि जिस में चुम्बी बैली पर बढ़ता हुआ दबाव किसी दूसरे रूप में परिणत हो क्योंकि चीन की योजना स्पष्ट मालम होती है कि एक बार पाकिस्तान को आगे करके हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया जाय और फिर आक्रमण करने के बाद हो सकता है कि वह फिर कुछ पीछे को लौटे लेकिन उस लौटने में भूटान और सिक्किम को वह अपने मुँह

में रख ले और नेफा का कुछ हिस्सा भी वह अपने अधिकार में कर ले। इधर पाकिस्तान का जहाँ तक संबंध है कच्छ और काश्मीर पर तो पाकिस्तान की आँख पहले से है ही अब पश्चिम बंगाल में भी उस के एजेंट काफी मात्रा में आ गए हैं। पीछे जब चीन को पाकिस्तान ने काश्मीर का कुछ भाग दिया, बदकिसमती से जिस पर सुरक्षा परिषद् ने सांस तक नहीं लिया, अब फिर चीन और पाकिस्तान काश्मीर में इस प्रकार की योजना बना रहे हैं कि कारगिल के पास लेह सड़क को काट कर लद्दाख के हिस्से को पृथक करें। भारत सरकार की स्थिति दुर्भाग्य से ऐसी है कि वह आदर्शवाद के चक्कर में आकर न सीमांत गांधी की पुकार सुनने को तैयार है और न पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की कराह सुनने को तैयार है। भारत और पाकिस्तान में उपाध्यक्ष महोदय, मौलिक दृष्टि से कुछ अन्तर है। पाकिस्तान की बागडोर एक सुलझाये हुए सैनिक अधिकारी के हाथ में है और भारत की बागडोर उन लोगों के हाथ में है जो जितना भी बच जाय उसी पर संतोष करके बैठे रहना चाहते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण अभी देखने में मिले हैं 14-15 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान का भाषण हुआ, तो उसने अपने भाषण में अपने देश की जनता से ही नहीं, काश्मीरियों को भी आश्वासन देते हुए कहा कि पाकिस्तान का एक-एक नागरिक तब तक चीन के साथ नहीं बैठेगा, जब तक काश्मीर को भारत से आजाद नहीं करा लिया जायगा। इधर बदकिसमती से 15 अगस्त को ठीक 24 घंटे बाद भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का भाषण दिल्ली के लाल किले पर हुआ। दिल्ली के लाल किले का भाषण प्रधान मंत्री का कोई सामान्य भाषण नहीं होता है, इस को देश भी सुनता है और विदेश भी सुनते हैं और वह एक एतिहासिक

[श्री प्रकाशबीर शास्त्री]

भाषण होता है। लेकिन इस ऐतिहासिक भाषण में, मुझे आप ये शब्द कहने की आज्ञा दीजिये, 1965 की सबसे महत्वपूर्ण घटना—पाकिस्तान और भारत के संघर्ष की चर्चा तक करनी प्रधान मंत्री ने उचित नहीं समझी। शायद उन को डर लगा हो कि चर्चा करने से पाकिस्तान नाराज न हो जाय। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का नाम तक अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने लेना उचित नहीं समझा। इसके अतिरिक्त जो सब से बड़ी चीज थी वह यह कि जो शहीद हुए थे—भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में—क्या वर्तमान प्रधान मंत्री एक शब्द कह कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर सकती थीं? यह एक मौलिक अन्तर है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है।

13 hrs.

[SRI P. K. DEO in the Chair]

एक और बात जिसको मैं विशेष रूप से प्रतिरक्षा मंत्री से कहना चाहता हूँ—वह यह है कि हमारी दुर्बलता पिछले तीन संघर्षों में जो रही और उसके जो मुख्य कारण रहे उसका मुख्य कारण हमारा सैनिक गुप्तचर विभाग (मिलिट्री इन्टेलिजेन्स) था। मुझे इस के सम्बन्ध में अच्छी तरह से याद है, जैसे तो इन्टेलिजेन्स इस देश का सारा खराब पड़ा हुआ है जब कि ए०आई०सी०सी० के दफ्तर में पाकिस्तानी भेदिये वर्षों तक रह कर चले जाते हैं और गृह मंत्रालय को पता नहीं लगता, तो यह सब गुप्तचर विभाग की शिथिलता नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि मिलिटरी इन्टेलिजेन्स से गृह मंत्रालय के इन्टेलिजेन्स के मुकाबले कुछ अधिक अपेक्षा की जाती है। पीछे जो नेफ़ा रिपोर्ट थोड़ी सी इस सदन में आई थी, जिसका कुछ भाग, श्री यहाँ पर पेश किया गया उसमें सरकार ने अपनी दुर्बलता छिपाने के लिये पूरी रिपोर्ट को पेश नहीं किया। लेकिन जितनी भी

पेश की गई, उसका मिलिटरी इन्टेलिजेन्स के फेल्योर से ही सम्बन्ध था। मिलिटरी इन्टेलिजेन्स ठीक न होने से उस वक्त जितनी चोट देश को लगी, क्या उसके बाद भी हम ने मिलिटरी इन्टेलिजेन्स को सम्भाला। उस समय जो उसके डाइरेक्टर थे, उसे क्या पुरस्कार दिया, उस फेल्योर का जो जिम्मेदार था। वह पहले ब्रिगेडियर था बाद में उनके पद को बढ़ा कर मेजर-जनरल बना दिया गया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? कच्छ में सड़कें बननी रहीं, पाकिस्तान तैयारी करता रहा, लेकिन मिलिटरी इन्टेलिजेन्स को पता नहीं चला। अभी इस समय जब पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष हुआ, मिलिटरी इन्टेलिजेन्स के फेल्योर के कुछ और उदाहरण भी हमारे सामने आये। समापति जी, मिलिटरी इन्टेलिजेन्स यह नहीं बता सका कि पाकिस्तान की सिक्सथ अर्म्ड कोर पेटन-टैंक्स से लैस है, उसको इसकी जानकारी नहीं थी। इसी तरह से जब हमारी सेना बढ़ रही थी तब बढ़ती हुई हमारी सेना को यह सूचना दी गई कि पाकिस्तान का जो पहला अर्म्ड डिवीजन है, वह भिम्बर की ओर बढ़ रहा है, जब कि सच्चाई यह थी कि हमारी सेना आगे चली गई और पाकिस्तान का फर्स्ट अर्म्ड कोर रायकिंड के पास इन्तज़ार कर रहा था कि कब भारतीय सेना आगे आये और पीछे से आकर उनको मारा जाय। यह मिलिटरी इन्टेलिजेन्स के फेल्योर का प्रमुख उदाहरण था।

इच्छोगिल कैनल के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी रक्षा पंक्ति तैयार कर रखी है, इसकी मिलिटरी इन्टेलिजेन्स को कोई सूचना नहीं थी और न वह कोई हवाई फोटो या किसी तरह की कोई अन्य जानकारी ही उसको दे सका। हमारा सैनिक गुप्तचर विभाग न यह बता सका कि लाहौर-अमृतसर के बीच में सुरंगें बनी हुई हैं और उन में रह कर पाकिस्तानी हथके की गारियाँ कर रहे हैं। वह तो धन्यवाद देना चाहिये उन तस्कर व्यापारियों को जिन्होंने भारत सरकार की

यह जानकारी दो कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं है लाहौर और अमृतसर के बीच में सुरंगें बना रही हैं। वे हमला कर के उन के अन्दर चले जाते हैं। न ही पिल-वाक्सों की जानकारी हम को पहले से थी। जो इतनी बड़ी जन-हानि हुई, जो हमारे जवान वहां शहीद हुए, उसका बहुत बड़ा कारण मिलिटरी इन्टेलिजेन्स का फेल्योर था। जो इन्टेलिजेन्स नेफा में फेल हुआ, जो कुछ आक्रमण में फेल हुआ और जो सैनिक गुप्तचर विभाग पाकिस्तान के आक्रमण में फेल हुआ उसके लिये मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ कि जब तक रक्षा मंत्री मिलिटरी इन्टेलिजेन्स का रि-ऑर्गेनिजेशन नहीं करेंगे, तब तक आगे आने वाली आपत्तियों से हम अपने देश को नहीं बचा सकते और न रक्षा कर सकेंगे; अगर यही लापरवाही बारबार होती रही। कुछ शब्द भारत-पाकिस्तान संघर्ष के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूँ। अन्त तक हम को यह पता नहीं लगा कि हम जो पाकिस्तान से लड़ रहे थे, आखिरकार हमारा उद्देश्य क्या था, जिसके लिये हम ने यह लड़ाई की। पाकिस्तान का उद्देश्य, सभापति जी, बड़ा स्पष्ट था। एक उद्देश्य पाकिस्तान का यह था कि वह पंजाब के जंडियाला-गुरु के पास जी० टी० रोड को काट कर ब्याम नदी के क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था दूसरा काश्मीर की अखनूर सड़क को काटकर वह काश्मीर घाटी को अलग करना चाहता था। 10 सितम्बर को प्रतिरक्षा मंत्री ने बयान दिया कि समूचे रूप में हम अपने उद्देश्य में सफल हो गये हैं। लेकिन हमें बताया जाय कि वह कौन सा उद्देश्य था, जिसमें हम सफल हुए। जब राजनीतिज्ञों के अपने मस्तिष्क ही स्पष्ट नहीं थे तो सेना कहां स्पष्ट हो सकती थी। इसका दृष्टपरिणाम जन और धन की हानि के रूप में हुआ लेकिन इस लड़ाई से ही कुछ सीखत तो भी ठीक था सभापति जी आप इसी से अनुमान लगा लीजिये कि इस लड़ाई से हम ने क्या सीखा? पाकिस्तान ने अपनी सेना के पांच डिवीजनों

को बढ़ा कर 11 डिवीजन कर लिये हैं, पाकिस्तान ने अपने टैंकों को जो खराब हो गये थे, उन सब की पूर्ति कर ली है। पाकिस्तान ने 110 मिग चीन से लिये, 90 सेबर जेट कनाडा से मंगाये और जो पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर है, उस में सैनिक संख्या को दुगना कर दिया है। लेकिन इस के बदले में भारत ने अपनी रक्षा तैयारी का क्या किया? हम ताशकन्द में समझौता कर आये कि 1949 में हमारी सेना की जितनी संख्या थी, हम उतनी कर देंगे। लड़ाई से यह सबक हम ने सीखा है और यह तैयारी हमें ने की है।

19 साल के बाद भी, हमारी जो 2510 मील की सीमा लाइन थी, उस में से भारत केवल 1९95 मील का सीमाकरण कर पाया है, पूरा सीमाकरण भी हम अभी तक नहीं कर पाये हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति हमारे पास तैयार नहीं है। एन० सी० सी० पर हम ने इतना व्यय किया है, लेकिन क्या रक्षा मंत्री अधिकारपूर्वक इस बात को कह सकते हैं कि एन० सी० सी० हमारी द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में काम कर सकेगी। क्या हम ने अपनी प्रादेशिक सेना को तैयार किया जो नेशनल मिलिशिया के रूप में काम कर सकती है। आप इजराइल को जा कर देखिए, जिस ने अपने ६3 प्रतिशत लोगों को राष्ट्रीय प्रादेशिक सेना बना कर तैयार कर दिया है, जो मोर्चों पर भी काम करते हैं, और खेतों में भी काम करते हैं।

मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते समय दो-तीन मिनट और चाहूंगा। सब से बड़ी चीज आज यह है कि अगर हमारा डिफेंस पूरा काम नहीं कर सकता, तो डिफेंस का एक दूसरा सहायक अंग भी होता है, जिसका नाम है डिप्लोमेसी। डिफेंस और डिप्लोमेसी—दोनों साथ साथ मिल कर चलते हैं। जहां डिफेंस फेल होता है वहां डिप्लोमेसी काम करती है। पाकिस्तान का डिफेंस फेल हुआ, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फेल नहीं हुई। 1967

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

के बाद चीन के साथ पाकिस्तान का सम्बन्ध हुआ, लेकिन आज पाकिस्तान ताशकन्द में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद रुस की गुड-बुक्स में भी है, चाइना की गुड-बुक्स में भी है और अमरीका की गुड-बुक्स में भी। पर हमारी अपनी स्थिति क्या है? जो पहले हमारे मिल थे, वे भी आज धीरे-धीरे हम से अलग होते जा रहे हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी अगर हम ने डिफेन्स के साथ अपनी डिप्लोमेसी सर्विसेज (कूटनीतिक सेवा) की सम्भाल कर नहीं रखा और यह देश अगर डिप्लोमेसी में दिवालिया हो गया, तो डिफेन्स प्रेपरेशन्स आपकी कितनी बढ़ती चली जाय, वे पूरी तरह से देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे। पीछे क्या हुआ? हमारे सिपाहियों ने जो कुछ अपनी शक्ति से लिया, उस को हमारे राजनीतियों ने एक कमरे में बँठ कर खो दिया। मोर्चों पर शहीद हुए जवानों की कुरबानियों को खत्म कर दिया। मैं ताशकन्द समझौते के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ने जो ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर किये उस पर मैं आज भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शास्त्री जी ने हस्ताक्षर किये नहीं, शास्त्री जी से हस्ताक्षर करवाये गये। शास्त्री जी का कलम उस दस्तावेज पर चली, लेकिन उनका दिल दस्तावेज पर नहीं चला। दस्तखत करने के बाद जब उस देशभक्त के दिल में आया कि दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद जब 16-16 और 17-17 साल की विधवायें सवाल करेंगी कि शास्त्री जी क्या इसी दिन के लिए आपने हमारी मांग का, सिन्दूर पूँछा था? जब छोटे-छोटे बच्चे पूछेंगे कि क्या इसी दिन के लिए आपने हम को भनाय बनाया था, जब बूढ़े मां-बाप पूछेंगे कि क्या इसी दिन के लिए हमारे बुढ़ापे की लकड़ी को आपने हमसे छीना था तो क्या उत्तर दूंगा? इस

का नतीजा यह हुआ कि यह बोझ वह देशभक्त बरदाश्त नहीं कर सका। मैं इसीलिए कहता हूँ कि यह सरकार कब तक इस फरेबी दस्तावेज से चिपके रहना चाहती है? जब पाकिस्तान के इरादे साफ हैं, तो यह सरकार ताशकन्द समझौते को एक भ्रोर कर क्यों नहीं अपना उद्देश्य स्पष्ट करती।

मैं शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जो ताशकन्द समझौते से रोष उभरा था, वह शास्त्री जी की मृत्यु के शोक में बदल गया। लेकिन इस रोष को अब आप अधिक देर तक दबा कर नहीं रख सकते। आज इतिहास ने पूछना शुरू कर दिया है, आज शहीदों की आत्माओं ने पूछना शुरू कर दिया है और आज देश की जनता ने भी पूछना शुरू कर दिया है कि ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हम को क्या मिला? कब तक हम उस मरे हुए समझौते की दुहाई देते रहेंगे।

अन्त में मैं यह कह कर समाप्त करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय संकट में सारा देश आप के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर रहा, और आगे भी बराबर रहेगा, लेकिन आप इस भूखे और नंगे देश को, इस गरीब और असहाय देश को बार-बार परीक्षा की कसौटी पर न लाइये। एक बार अब अगर आप खड़े हों, तो कम से कम शत्रु को ठिकाने तक पहुँचाइये। शत्रु को ऐसा दंड दीजिये जिस से वह आगे कभी इस प्रकार का दुःसाहस न कर सके।

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): Mr. Chairman, the hon. Defence Minister's statement contains facts and figures indicating the frantic efforts which Pakistan has been making to reinforce and rearm itself from all the quarters of the globe and the state of affairs it has achieved. I assure him and the House that we do not feel alarmed about it. We definitely feel deeply concerned, naturally because Pakistan has not done all this simply for nothing. It must have a definite purpose. So, it is

necessary for us to analyse the whole situation in an absolutely objective manner and try to understand the responsibility thrown on our shoulders. I have no hesitation in saying that the Defence Minister inspires confidence in us. While I fully appreciate what my friend, Shastriji, said about our military intelligence—we also want that our military intelligence must be streamlined and should give a better account of itself—but the very fact that the Minister has given us a very graphic picture of what is happening in Pakistan in regard to armament and over the boundary on the other side indicates that our military intelligence is not lacking and it has taken note of the developments. The Minister has rendered a great service to the country by putting all these facts and figures before the House and the country. Not that we get alarmed, but we all take a share of our responsibility and chalk out a line for ourselves.

I also agree with the previous speaker that it is not only military force which counts. Military force is very vital and it will deliver the goods. But far more important is our diplomacy and the conditions on our home front.

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): Civil Administration.

Shri Harish Chandra Mathur: That is what operates at the home front. It is in this context that I regret what has been said by the great leader of the Swatantra Party, Mr. Rajagopalchari, the insinuation he has made against the statement made by the Defence Minister, as if it was made to create a scare and gain some political advantage. It is most regrettable. The statement has been made by the Minister to warn the country and the members to make a correct appraisal of it. Let us not be carried away in these vital matters by political consideration and electoral fringes.

It is obvious that Pakistan and China are in collusion. The External Affairs Minister said in the other House only

yesterday that China is toeing a tough line and we should take note of that fact. It is not only diplomatic support which China is giving to Pakistan. It has gone much further and given to Pakistan all the military hardware which Pakistan really needs—tanks, etc. which they were not getting from elsewhere. China has announced not only from house-tops but from the roof of Himalayas "We are there to support you". Has any other country told us like that? We do not expect any other country to tell us like that. So, there is China on the one hand.

On the other hand, USSR is soft-peddalling the whole thing. It has its own interest. I still consider USSR to be our sincere friend, but it also wants to enter into relations with Pakistan and advance its own diplomacy. It will definitely give priority to its own interest rather than to our interest. Its interest has been identical with our interest all this time, but now there has been a shift. While we fully appreciate the assistance given by USSR to us till now, let us be clear that there has been a shift and it wants to have friendship with Pakistan.

It is a little surprising that the western democracies are not less interested in Pakistan. Mr. Morarji Desai, who is considered to be leaning towards western democracies, himself felt it necessary only the other day to administer a warning to them that they were encouraging and instigating Pakistan in more than one way. Let us take note of that. West Germany has openly passed on 90 Sabre Jets to Iran and from there they have come to Pakistan for repairs! It is adding insult to injury to both our intelligence and to the intelligence of anybody. Who is thinking that the jets have come to Pakistan for repairs? If anything, Pakistan has not been able to repair the hardware damaged in the last aggression. This camouflage is too thin. We have got to make our position absolutely clear and clean to these powers. My hon. friend laid so much stress on diplo-

[Shri Harish Chandra Mathur]

mac y. Diplomacy will take care of itself if you have a clear mind, clear vision and a firm attitude. It is only that a proper adjustment can be made with other countries. If they go on probing you and they find there is a place to go so far, they will naturally get to that extent. But if they know that they can go only so far and no further, that India will not tolerate any nonsense and they will lose the friendship of India, then a better adjustment will come; there is no doubt about it. That will come only if we are absolutely firm in our mind and clear in our vision and if we are not prepared to compromise and appease. You can trace the history of a century; the policy of appeasement has never paid anywhere in the world. It has been always a failure. Let us be clear about that.

I am most intrigued by the attitude of the United States. In Vietnam they are spending billions of dollars and getting their young boys killed, for the purpose of containing China. If they are really interested in containing China there, how is it that they are getting so friendly with Pakistan, in spite of the hardware coming from China to Pakistan? They could not find hardware worth even Rs. 60 crores from 1962 to this day to be given to India for being purchased. They must have spent billions worth of hardware in Vietnam where their purpose is to contain China. What will they do if the Chinese aggression creeps further to Thailand, Cambodia and Burma? Are they going to go the same way or are they having a little wisdom now to strengthen these countries in time? It is most intriguing and I do hope that the Defence Minister will be able to throw some light on this.

I also want to give a warning to the Defence Minister. We want, of course, to normalise relations with Pakistan. I do not want that he need bang the door. He may do all that is humanly possible to normalise relations with Pakistan. But if you go to their door

and they bang the door in your face, you are not advancing your cause. That is not the way to normalise relations. Normalisation can come only when there is willingness and agreement on the other side. Till then, I ask the Government not to go out of its way and create a wrong climate by approaching them all the time for this meeting or that meeting in a purposeless manner. We must make our attitude perfectly clear. We want to normalise relations; we do not want aggression. But we are not going to follow a policy of soft-peddling and appeasement.

If Pakistan, as Pakistan appears to be, is determined, if it has made all these preparations, if it is wanting to brow-beat us and because China is prepared to help her she wants to serve as an instrument of China for her own destruction by coming on a war with us, this country will never excuse this Government next time if it stops short of not taking the war to its logical conclusions. The logical conclusion is the evacuation and taking possession of the part which is at present occupied by Pakistan. Let it be perfectly clear to Pakistan that next time there is aggression by them—Bhutto may be saying anything, it may be a hundred years war, but we have to depend on ourselves—the war will not be stopped and that war will be taken to its logical conclusions.

I also want to remind the hon. Defence Minister of what he said at a public meeting which he addressed in Jodhpur after the cessation of hostilities. What happened last time was that Jodhpur, which is a border place, went absolutely undefended. But the brave people of that place never evacuated. They gave the fullest cooperation to the Government. They stood their ground. Even the children stayed in their place in spite of the fact that 202 bombs were dropped in that place. There was not one aeroplane to go and meet the bombers which were coming from the side of Pakistan. That was the state of affairs. But the people of that place gave an

exceedingly good account of themselves. The hon. Minister said in that public meeting that next time there is an aggression it is not bombs which will be dropped but it will be the bombers, if they come, which will fall down here. I hope he will be able to repeat that assurance which he gave to the people of that place and I hope he has taken necessary measures and steps for that purpose.

I wish, again, to invite his attention to the difficulties in Rajasthan over the border check posts. What happened last time? We had to vacate some check posts because we wanted a good grouping of certain selected ones. Pakistan stealthily came and occupied those check posts, which had been vacated by us, after the cease-fire and created all the trouble for us. I read only in today's papers that Pakistan is strengthening her check posts all over the Rajasthan border and putting all the people there. Therefore, we have also to take steps to strengthen our check posts on our border on the Pakistan side. We must try to see that these things are done in an effective manner, and if Pakistan is made to feel, if other countries are made to feel that we are fully prepared and determined, I think a clash may be averted, but all depends upon how firm we are and how we make our friends feel about it.

Shri Krishnapal Singh (Jalesar): Mr. Chairman, Sir, we have every reason to feel grateful to the hon. Member who has moved this motion. He has rendered the country a great service by drawing attention to this issue at this very critical moment.

Sir, defence is a costly business. At the present moment, weapons and machines which are employed in defence cost a good lot of money. The first thing we have to think of is how to find sufficient money for our defence. As I said the other day, we have to think of winding up our planning business in order to find sufficient money. The reason why I said this was that so long as this planning organisation lasts they will always prepare costly schemes in order

to justify their very existence. Therefore, I think we must cut down our expenditure, cut down our Plan, shelve them for a little while and devote large amounts of money to be spent on defence and agriculture.

When the Supplementary Demands came up before Parliament, I said that very little money had been allotted for development of our navy which is so very deficient at present. We know that the entire method of constructing ships has been completely changed and revolutionised. A complete metamorphosis is taking place. We hear that submarines are being planned which will crawl on the bottom of the sea. There are other kinds of ships which are specially built to act as defence against air raids. There are aircraft carriers worked by nuclear power, there are other types of ships which have nuclear power. When we think of all these sophisticated machines we find that we have not got a single ship which can be compared with these vessels.

Then we come to the army. I will not mention the controversial atom bomb but, I would like to mention and, I was glad to read the other day, that our Chief of Army Staff said that he would be glad to have some missiles. Missiles have come to the forefront in the scheme of the defence of every modern country at present. There are ground to air missiles, air to air missiles, all kinds of missiles. There are missiles of 8000 miles range, of 2000 miles range, medium range missiles. Now, Sir, I would like to know if we have been able to satisfy the anxiety of the Chief of Army Staff to have some missiles for his army. That is one thing in the range of weapons. So far as rifles and other weapons are concerned, other countries, countries like America, are thinking of having automatic rifles which can fire about 7000 rounds per minute. Although we recently developed an automatic rifle of our own, we have not yet been able to have a weapon for our army which will be anywhere near what the American weapon at present is or the American army is aiming at to have.

[Shri Krishnapal Singh]

My real point is, in order to possess these weapons, self-sufficiency is very good but if we cannot be self-sufficient for the time being, we must, by some hook or crook, try to acquire modern weapons for our armed forces from anywhere we can get them.

The second point I would like to mention is regarding security. Enough has been said about intelligence. Intelligence is the system by which we acquire information of defence value about the enemy's armed forces. Security deals with the denial of that information to the enemy. Our security, unfortunately, has been very bad for the last few years. One reason is that we have permitted people from every country to wander in India freely. They have been able to know where our defence installations are, what type of weapons our armed forces possess and what their training is. We have had no restriction. In a country like Russia or China this kind of facility would not be possible. Therefore, we should tighten our security a lot. The other day we found that an official of the All India Congress Committee was involved in helping Pakistani spies, I am informed by one of my hon. colleagues that there is a member on the staff of the Trombay organisation who has some very good and close contact in Pakistan. Now, that sort of thing should be noted very carefully and we should weed out all such people and, naturally, we should do it in time.

The third point I would like to mention is about finding an ally. As I said, self-sufficiency is very good. We should try to be self-sufficient. But, so long as we are not self-sufficient, just as Pakistan is able to get weapons and is able to have a dependable ally, we should also try to get one. Here I may be permitted to say that we shall have to make a certain amount of sacrifice of our idealism. We have been too idealistic and, on account of this idealism, we have not taken a practical view of things. I will quote just one example. Whenever we need

food, we go to America and they always help us. It is very good that America is giving us valuable food. But, whenever they do something in Viet Nam, we start criticising them. If you ask for help from a man, it is only natural that you must refrain from criticising him. I am not going to say that whatever America is doing is right or wrong or justified; I am not going into it. I am only trying to emphasise the need for being practical. Therefore, I would like to impress upon the Government that whenever we deal with other countries which have been friendly to us throughout, we must refrain from criticising them. We must make an effort to secure really reliable friends on whom we can depend in times of need.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Chairman, Sir, I congratulate the Defence Minister for giving us a very factual statement about the military preparedness of Pakistan. I also feel like congratulating our military intelligence.

But I want to submit very respectfully that, so far as the defence preparedness of Pakistan is concerned, it follows the methods of businessmen. As businessmen have three different types of books, one for the income-tax officer, a second for the partners and a third for private consumption, similarly, Pakistan has also three kinds of books of military preparedness. One book is shown to America and so it has got so many alliances like SEATO, CENTO and NATO. I indict America for supplying Pakistan with all kinds of military hardware and equipment, knowing full well that Pakistan was not going to fight Communism. Now my information is that USA is making use of the good offices of Pakistan in order to build a bridge between USA and China. That may or may not be the whole truth, but I think it to be the truth. So, one of the books is meant for that.

The second book is meant for their newly-acquired friend, China. What is common between China and Pakistan? The only thing that is common

between them is utter hatred of India. China has supplied them tanks, MIGS and other things. China has also assured them that they would not desert them, leave them. When we were fighting the Pakistani aggression, China gave us an ultimatum. So, China is doing that.

The third look of military preparedness is meant only for the military dictatorship of Pakistan. Now, what that picture reveals, I think, will be too terrible to contemplate on the floor of this House, if I peer into the future. I can tell the hon. Defence Minister that last time the fight was with the help of tanks and bombers, but next time the fight is going to be, on the side of Pakistan, not only with the help of tanks and bombers but also with the help of guided missiles. They have already set up a base of guided missiles in East Pakistan with the help of China. If I may not sound too alarmistic, I may say that some kind of crude atom bomb, some kind of crude atomic appliances, may also be used in that war.

Therefore, I want the Defence Minister to understand that the future of our relations with Pakistan depends not on diplomatic moves. My hon. friends have been talking about diplomacy. We have tried diplomacy all these 18 years and the result has been on the minus side. Our diplomacy with Pakistan has failed. I think we have reaped more harm than good from that diplomacy. My friends have been talking about making our relations with Pakistan normal. Has any country in the history of the world done more to normalise its relations with its neighbours than we have done? But, what has been the result? Nothing. Therefore, the diplomatic level, the normalisation level is not going to count; it is only the show of arm by India that is going to count. If we are strong, tough and unbeatable I think we shall be on the road to normalising our relations and to success in our diplomatic missions. Therefore, what is required is sword-

manship. The defence-consciousness should be created all over India.

People will say that I am talking the language of a war-monger. If I am dubbed as a war-monger, I would be very happy, because I would be war-mongering in the interests of the safety, defence, integrity and sovereignty of the country. But I would say to our hon. Defence Minister that I am proud of our army, I am proud of our Defence Minister. But I would say that this defence-consciousness should start from the bottom and reach the top. It should pervade all of us. Of course, I know that in one of the units of India they are trying to overhaul the syllabus in the interests of defence-preparedness. But I do not know when it will bear results. Anyhow, defence-consciousness is the most important thing that has got to be done.

Then I come to the second thing that has got to be done. I would request him to take a little more care in the border areas. What has happened in Khem Karan or Gurdaspur or Dera Baba Nanak or Fazilka? If we were to go there, we will find that the people do not feel happy with what has been done to them. The other day an old lady came to see me and said, "My son is in the border security police; he has been posted in Fazilka; for God's sake, please see that he is released from there". I said: "No, no; go to somebody else; go to some Swatantra Party man or some other party man".

Then, the border areas, checkpoints and border security force should be made as strong as possible. I understand these things much more than anybody else, more than the Swatantra Party does. The border security force is in the hands of the Home Ministry which is probably a hesitant and wobbly Ministry. It is like that all over the world; I am not saying that it is like that here alone. This kind of Home Ministry should be rid of this possibility of looking after the border security police. It is a hangover from the British rule and the sooner we do away with it, the better it is.

[Shri D. C. Sharma]

I would, therefore, say to the hon. Defence Minister to take the border security police in his own hands and not to let the Home Ministry of this country have anything to do with it. The future is very dark, Pakistan is preparing very hard and we should do our best to meet it.

Shri Indrajit Gupta (Calcutta South West): Mr. Chairman, this is neither a full-dress defence debate—it cannot be—nor a debate on foreign policy. I would remind the Members that we are only five days distant now from the anniversary of that fateful day when the Pakistani Armoured Corps struck across the Chhamb-Jaurian border and at a time like this if we are to have this discussion at all, I feel strongly that it should have been on the basis of something more substantial than this statement which has been given to us. This statement is totally unsatisfactory. This debate, I am told, is on this statement. I do not know, I was not here for most part of the time.

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): That is true.

Shri Indrajit Gupta: Anyway, my point is that this statement, the initial statement, tells us nothing. I leaves us no wiser than we were before. This kind of statement might have been all right prior to 1962, but considering everything that the country and our people have passed through in the last four years and considering the experience we have had and the knowledge we have gained, even if it is layman's knowledge, I think, this kind of a statement does not do any credit to this House at all. It is not only unbalanced in the sense that it talks vaguely of the Pakistani build-up without giving us much material—whatever material we elicited later has not come from the Government; it was elicited by Members of the House through repeated questions and various other ways—on the other

hand, it says only in one concluding sentence:—

“the House may rest assured that Government are alive to their primary duty of maintaining the security and territorial integrity of the country and will deal with any development according to the needs of the situation.”

It is a perfectly useless statement.

Now, the Pakistani military build-up is going on and it is nothing surprising; it is nothing unexpected because we know that their attitude to Tashkent is completely negative and destructive. We also know that the influences that are playing still on Pakistan, whether of the United States or of China, are basically hostile to India. Therefore, a build-up by them is nothing unexpected or surprising.

Of course, in Pakistan Ayub Khan is telling his people every day about the Indian build-up. We read his statements too. He is telling Pakistan that India is doing a terrific military build-up and, therefore, Pakistan has got to take measures to defend itself. I do not want that there should be a competition of this type of statements to their respective countries by Ayub Khan there and the Defence Minister here. We must have some facts if we want to discuss seriously anything. This statement tells us nothing new.

The new thing in the whole situation, different to what it was a year or a year and a half ago, is what is being briefly mentioned or referred to by some hon. Members. The fact that replacements for the armour and the planes which were lost by Pakistan in last year's hostilities have been more than replaced by basically the same source of supply which was supplying them earlier, namely, the United States but by proxy—not directly but by proxy; either via West Germany or via Iran or via Turkey or via some other country—is what is new in the situation. But this statement does not contain that. Those facts had to be elicited here by calling-attention notices, questions and so on. Why it is not stated here is because our

Government has got certain relations with these countries of the west like Germany and America and we are so busy taking aid from them and asking for more aid, more loans and more food supplies that we dare not say anything here officially which we think may upset them.

I do not understand what is the purpose of this statement at this moment. If the statement is made to create a feeling of confidence in the country that despite anything that Pakistan may do we are more than well prepared to meet that, then that way also this statement contains no information whatsoever. Surely, it is not meant to divert the people's attention, as it were, from other internal problems. That will become a political motive then. So, what is the object of this statement? I fail to understand that. Or you must tell us that if Pakistan is doing these things, we are also doing something.

I take it that we are not sitting tight or idle and doing absolutely nothing, because if we are doing nothing and only they are building up then he will get into another trouble at our hands for we have voted a very big amount of money for defence. So, either say what we are doing or do not say that they are doing these things. building up all these things and so on.

In 1962 we suffered serious military reverses at the hands of the Chinese and in 1965 to some extent we were able to make good the earlier shortcomings and lapses and managed basically to defeat the aggressive designs of Pakistan. That is true, but that does not mean that any of us have forgotten the serious lapses and the initial unpreparedness with which we were confronted even last year. We have not forgotten the fact that five days hence the day, which we are going to remember the anniversary of, when the attack was made across the Chhamb-Jaurian border by the Pakistani Armoured Corps there was no air cover and that our entire Air

Force had to be diverted from everywhere else to Chhamb-Jaurian to halt that attack, to check it and to slow it down. We have not forgotten that when our army crossed the Lahore border to make a diversionary attack, for several days in the beginning there was no air cover whatsoever with the result that our forces went across the Ichhogil Canal and were driven back. We have not forgotten that the military transport system proved totally inadequate and we had to call all private lorry and truck drivers to come to our rescue. We have not forgotten these things.

We are not told anything about what is happening. We are not told whether those supplies from Britain particularly which had been contracted for before the hostilities broke out and which included valuable equipment, spares and armour plates for the tank factory at Avadi, have been properly resumed or not. Have we received those or what is happening; we do not know anything.

We were told that this plate material was going to be made at Rourkela which will ultimately supply armour plates for tanks. I was surprised to read only two days ago in the papers that Shri Rao, Chairman of the Hindustan Steel Limited, is now proposing to make a trip to Bonn—the same Bonn which is supplying all sorts of things to Pakistan—to negotiate this problem of Rourkela plant's expansion—operation problems of the Rourkela plant—and credit facilities for the project to manufacture armour plates. It says:—

"The need for technical personnel for this project would also be discussed."

After all this time it seems that the project for producing armour plates for our tanks is still at this stage. This is the position. Why should we not have misgivings then? We do not know what is happening. We are depending for this project on that same country which has been reported,

[Shri Indrajit Gupta]
without contradiction by anyone, to be supplying all sorts of things, including Cobra anti-tank missiles, tanks, planes, replacements and equipment for ordnance plants to Pakistan by means of some secret agreement and which has allowed these jet planes from Canada to be diverted via itself through Iran to Pakistan in the ridiculous name of there being no overhauling facilities anywhere else. To that same country we are going now for a project for building armour plates in Rourkela.

We do not know whether the British who are supposed to equip the Avadi factory are standing up to their commitments or not. There are so many other things which I have not the time to say. All I am saying is that we would like at least to know whether the losses that we suffered in tanks, equipment, planes last year have at least been replaced. I am not talking about building up further potential and all that, but whether those have been replaced or not we do not know.

Then, what about the MIG project? How is it advancing? We do not know that. We suffered quite heavy losses in tanks. Everybody knows it. Have those tanks been replaced? We do not know that. We do not know anything. Therefore this kind of a statement is really quite useless. Though I do not agree at all with Shri Rajagopalachari—somebody quoted him—but I must say that, in the absence of anything like that, in the absence of facts and figures and in the absence of any kind of information, I do not think that these things can be dismissed in the name of security. In the past on certain occasions Mr. Chavan has given us much more information than this. But I must say that if he gives this kind of statement, then it does open the way for suspicion to be created in some quarters that this is nothing but a means to divert the people's attention. I do not want him to supply unwittingly any ammunition to his colleague in the Home Ministry to say that while

there is a big threat developing on the border, you people are going in for bandhs, strikes, satyagrahas, morchas, etc., and you must be repressed and suppressed.

Finally I will only say that if you are anticipating any imminent danger or attack from Pakistan, as far as it is possible to anticipate, please say so. I do not find any such perspective contained either in the Prime Minister's speech from the Red Fort on the 15th August or in the Rashtrapati's address on the 14th August; in fact, their emphasis is different altogether. Therefore, please tell us what are they doing, how far do you know about it and what are we doing. Unless these two are seen in proper balance and perspective, it is useless to have this kind of statement.

Shri Brij Raj Singh-Kotah (Jhalawar): Mr. Chairman, it is very nice to read the statements made by the hon. Defence Minister and for taking the House into confidence. After reading it, one comes to the conclusion that Pakistan, through its unmatched diplomacy, as far as we go, has secured arms from both West and China to build up all the losses that it sustained from us and it leaves us, as far as I see, high and dry, dependent only on our own selves, which is a good thing as far it goes; but we have to take the wider context in view.

I will confine myself only to certain problems because the time is not much and I have also not many points to make.

I will take the Rajasthan border region and request the hon. Minister to consider, if not already implemented, certain points which to my mind are very necessary for the defence of that region.

First I would like to say that our border needs to be cleared of civil population over a belt of 15 to 20 miles deep from the border. I remember when I went there during the hostilities last time....

Mr. Chairman: May I ask the Minister how long he will take to reply?

Shri Y. B. Chavan: At least 15 to 20 minutes.

Mr. Chairman: Then I will request the hon. Member to confine his observations only to five minutes.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): How is it possible to finish in five minutes? You must give us at least ten minutes.

Shri Brij Raj Singh-Kotah: Why should I be penalised?

Shri Surendra Pal Singh (Bulandshahar): Is it not possible to extend the time for the debate?

Mr. Chairman: If it is the wish of the House to extend it, I have no objection.

Dr. L. M. Singhvi: It is such an important thing. The time should be extended by at least one hour.

Mr. Chairman: If that is the wish of the House....

Some hon. Members: Yes, yes.

Shri Brij Raj Singh-Kotah: May I continue for ten minutes? I was saying that....

Mr. Chairman: Is the Defence Minister prepared to extend it to some other day?

Shri Y. B. Chavan: I do not mind it, if it is the wish of the House. I am completely in the hands of the House.

Dr. L. M. Singhvi: It is heartening to find that the Defence Minister agrees to it, if the House agrees. The time should be extended because it is such an important matter.

Mr. Chairman: All right. The time is extended by two hours more. The hon. Member may take ten minutes.

Shri Brij Raj Singh-Kotah: I was saying that our border region on the 1516(ai)LSD-8.

Pakistan-Rajasthan border—needs to be cleared of individuals who are not desirable...

Shri Shinkre (Marmagoa): Will it be taken during this session or some time afterwards? The matter is very urgent.

Mr. Chairman: It is for the Government to decide.

Shri Shinkre: Let the hon. Defence Minister make a statement. Will it be taken on Monday?

Shri Y. B. Chavan: I cannot say that. It is for the Business Advisory Committee to decide.

Mr. Chairman: It is for the Government and the Business Advisory Committee to decide.

Shri Shinkre: The matter is very urgent and it is very important also. Let the Government not take refuge by postponing it to the next session.

Mr. Chairman: The Minister of Parliamentary Affairs will make a statement at 5 o'clock about the business for the next week. At that time, the hon. Member can make the suggestion.

Mr. Brij Raj Singh-Kotah may continue his speech.

Shri Brij Raj Singh-Kotah: I was saying that it reminds me that when I was there,—and I also know it for a fact—when during the hostilities certain battalions were moved up to Barmer under cover of darkness, the very next morning at the first light the Pakistani jets came over and bombed those battalions; this shows that there are undesirable elements who have a very good net of fifth column across the border. There are so many other instances which I need not repeat.

The second thing which I want to say is about the road system. The road system in this region is absolutely inadequate. It was proven last time and it will be shown every time that, if there are no roads, the troops can-

[Shri Brij Raj Singh-Kotah]

not go within the time needed to the outposts on the borders. The region is absolutely sandy and camels and men take at least six hours, if not more, to traverse a distance of 30 miles. How can we sit back quite contented without building these roads? I am told—I do not know—that we want to build a lateral road at least 15 miles behind the border. To my mind that is rather distressing. If you have to rush the troops to the border in times of need, and emergency, you cannot do so unless you have a road right next to the border. It is no good saying that if we have a road next to the border, the enemy might use it; because the enemy has already a road, hardly five miles inside from his side of border. If he can use it, he can jolly well use the other five miles or so. So it makes no difference.

I now come to provision of water in the outposts. I do not know, but I am told that certain experts have launched a scheme of piping water to these outposts. I do not know whether it is true or not. It is for the Defence Minister or the concerned authorities to give us the news. If it is a question of bringing water to these outposts by pipes, you can see the ridiculous extent to which our experts can go. Pipes are the easiest things to be sabotaged and when the pipes are sabotaged, what will the men at the outposts do? They will thirst for want of water. It must be borne in mind that so far as provisioning of water is concerned, the outposts must be self-contained. We can have that old system of "Tankas" we have in the deserts, i.e., we can have cisterns dug inside the ground whereby rain water plus the water provisioned by tankers could be kept inside the outposts, so that in times of emergencies the outposts are assured of supply of water for at least three or four days before relief or help can come.

I would also like to say that our area—Jodhpur, Barmer and all that

region—which suffered during the air-raids has to be further strengthened and it has to be shown, as Vietnam has shown, that it is not only the sophisticated anti-aircraft missiles that can bring down the planes; but if a good and adequate complex of ordinary anti-aircraft guns, i.e., the old World War II Model guns, are provisioned it can still wreck effective havoc on the enemy's planes.

I would also like to say that we must, in no uncertain words, give a stern warning to the West, specially to West Germany and Iran, for the way in which they have handed these "sabre-jets" for so-called overhauling to Pakistan. Today, there is a news item in the papers saying that Iran has promised to take them back. I only hope that Persian promises are as durable as the Persian carpets.

I have always thought that if we have to rely on ourselves, we must have a nuclear deterrent. It is no good thinking of nuclear abstinence or nuclear umbrella.

14 hrs.

Dr. L. M. Singhvi; Nuclear brahmacharya.

Shri Brij Raj Singh-Kotah: The only realistic policy is to have an independent nuclear deterrent. I would like to know whether any studies are being made on this subject and if so, what are the results? What are the findings? And what the nation can expect? The time has come in my opinion when every Indian has to debate very seriously everywhere, whether we want a nuclear deterrent or not. It is no good saying that we are going to practise, as Dr. L. M. Singhvi has said, nuclear brahmacharya. The other day it had come out in the papers that the new Chief of the Army staff, Gen. Kumaramangalam, had said in no uncertain terms that we should go in for missiles and there was no question about that. This nation has a right to know what we can expect in regard to this particular matter. Enough has been done to

make a small embryonic beginning of a project in the Bharat Electronics and other such allied concerns, but much needs to be done now, for implementing the missile needs.

14.03 hrs.

[SHRIMATI RENUKA RAY *in the Chair*]

During the last conflict, all our Armed Forces did a magnificent job, and a lot of decorations for valour were awarded. I have a feeling which, I think, is fairly well prevalent in the country, that most of the decorations went to the top leadership in the Armed Forces. As far as that goes, I have nothing to say, but I do feel that the unmatched gallantry shown by our young leaders, the captains, the lieutenants and the younger type in the hierarchy of the military has gone unrecognised by and large. I wish that this had not been so, for it leaves a little bad taste among the younger officers and men who had to do all that rough work, and see that only certain big officers commanding the battalions or the divisions or the corps got the topmost awards. I do not say that they do not deserve it; they have deserved it well by every right, but I do say that the younger brave soldier who risked his life and achieved what he did has also got to be recognised.

Shri Y. B. Chavan: They have been recognised.

Shri Brij Raj Singh-Kotah: But not enough.

Dr. L. M. Singhvi: We know Shri Y. B. Chavan to be a man of few words and of a stout heart. He is not used to crying 'Wolf' needlessly. I would, therefore, not assail this classic exercise in brevity which his statement of 1st August, 1966 represents. In him we know that we have neither a lighthearted nor a reluctant Defence Minister, and, therefore, I would say that in spite of the fact that this statement of his contains very little information to reassure us, I would lay

my faith in the assurances that have come from his stout heart.

The skies today are overcast with gathering clouds of aggression, of international intrigue and collusion. We are confronted today with menacing postures, not only from Pakistan but also insidiously from China. We know that the greed and the territorial ambition of Pakistan is insatiable. We know that the former Minister of Foreign Affairs in Pakistan had asked for a war for one thousand years, and it seems that even the present Government in Pakistan is determined to have a war for one thousand years and to fulfil their desire for war. It seems that our conciliating approach to the problems that conflict the relations between these two countries have continuously whetted the appetite of Pakistan and have given rise to these menacing postures. It seems that Pakistan is determined to wreck the Tashkent Agreement which perhaps they did not enter into in good faith. It seems that the Defence Minister's statement is an epilogue to the well-meant efforts at mediation which were initiated by the Soviet Union and which culminated in the Tashkent Agreement.

We find today that Ichchogil type canals are being constructed by Pakistan. We know for sure that Kasur nullah is being improved for military purposes. We know that in this Pakistan has disregarded and thrown to the winds the Indus Waters Treaty which restricts the use of the Kasur nullah for purposes other than military ones. We know that there is a missile base under construction in Kosthia in East Pakistan and Haliped somewhere in Chandrapir. We know that Pakistan is constructing structures in the vicinity of the Suleimankh headworks.

We know that there are intrusions after intrusions on all sides of our borders and yet we are told that there is nothing very much to worry about and Government are seized of the problem and will take adequate care of it.

[Dr. L. A. Singhvi]

The involvement of Pakistanis with the Nagas and Mizos and their active participation in programmes of training for Pakistani soldiery in guerilla warfare and espionage and the Chinese activity near the Chumbi valley as well as in respect of Sikkim and Bhutan give rise to apprehensions and misgivings in our minds. I would like that the Defence Minister lays some of these apprehensions and is able to give us ascertained facts on the basis of which a resurgence of national awareness and defence consciousness can be generated.

It seems that in the matter of receiving equipment, Pakistan has bettered even its own expectations. Only the other day, the hon. Minister informed the House that the Pakistan Air Force had five more squadrons of fighters and bombs than it had last year and that it had decided to raise its armed strength from five to eleven divisions. The hon. Minister went on to inform us that he was getting the active help and co-operation of the Chinese who had not only supplied two hundred tanks and scores of MIGs but also provided credit to shop in the West Asian countries for military hardware on a cash-and-carry basis. He also told us that about 110 aeroplanes which were of Canadian origin were routed from West Germany to Iran and from Iran to Pakistan ostensibly for the purpose of repairs. I should like very much the Defence Minister to tell us if his inquiries in this respect have enabled him to reach any definite conclusions, whether those planes were diverted to Pakistan as a part of Iran's active assistance against India and whether we have been able to take up this matter diplomatically with Canada, West Germany and Iran and if so, with what effect. It seems that Portugal is another offender and with them I suppose we cannot even take up the matter diplomatically. But the magnitude of these involvements, the magnitude of this conspiracy and the magnitude of this treachery and per-

fidy should be known to this country so that we are not caught unawares as we were in 1962.

I should like particularly to know as to what is the position in respect of missile bases in Pakistan. Are Government aware and cognisant of all the implications of the nuclear pact Pakistan has entered into with China? This nuclear pact between Pakistan and China seems to be an extension of the Chinese nuclear blackmail which is spreading its tentacles diplomatically and in defence terms throughout the territories of Asia. Neither nuclear celibacy nor nuclear promiscuity or indulgence would show us the way for policy formulations. We want to know how far these nuclear negotiations and this nuclear relationship between Pakistan and China have gone. You would recall that Pakistan launched an attack on India recently saying that we are trying to develop nuclear weapons. Largely, it seems to conceal its own designs for initiating a programme for developing its own nuclear weapon capacity. I should very much like the Defence Minister to tell us more about this. India does not want to grow into a nuclear spinsterhood and into a kind of frustration in terms of international diplomacy and in terms of defence.

It is true that Mr. Bhutto has gone, but it seems that his ghost still haunts the policies of Pakistan. It seems the ghost is more powerful than Mr. Bhutto was himself. Only the other day Gen. Ayub stated that no negotiations would be had with India unless we were prepared to talk in meaningful terms on Kashmir.

I would like particularly to refer to certain problems concerning Rajasthan. The Defence Minister himself visited Jodhpur and was good enough to ask some of us to accompany him and apprise himself about defence problems in the border regions of Rajasthan. At that time, he had given certain assurances in a public meeting. He said on an earlier occasion on the floor of the House when I rais-

ed this question that he meant to stand by every word of those assurances. There is considerably anxiety today. The city of Jodhpur was the most heavily bombed city in the entire country in last year's hostilities. It had received, according to the latest count, as many as 215 bombs in that area and it was largely undefended until the Defence Minister very kindly sent some anti-aircraft guns at a rather late stage. It seems that the entire belt near the Rajasthan border is inhabited by certain people who have extra-territorial allegiance, and the mischief that the Pir of Pagaro and his men can create in that area constitutes a menace to our security. I would like the hon. Minister to take note of this. There is news of infiltration in the Rajasthan border and near the Rajasthan border. Neither is the present dispensation in the border area sufficient nor is the State itself able to handle this entire problem of infiltration, of espionage and of active subversion in that area. The equipment of the armed constabulary in that area is very poor. Therefore, the Army has to take over.

I would only like to emphasise the fact that unless development takes place so that there is water and there is other development in the field of agriculture, this area cannot be defended adequately, as was demonstrated during the last conflict with Pakistan. I should like the hon. Minister to give us an adequate reply about the arrangements he is making for the adequate defence of Rajasthan so that the story of surrender of large territory, the story of humiliation in that part of our border is not repeated. I know that he would be able to give us an adequate answer to the glory of this country.

Shri Himatsingka (Godda): In his statement, the Defence Minister briefly set out the preparations that had been made by Pakistan. He also very clearly indicated that he was aware of the situation and was taking all possible precautions necessary

to defend the country and that there was no need for any alarm on fear. Naturally, he cannot be expected to give out in detail the preparations that have been made or are being made. But he assured the House that he was aware of the situation and was prepared to meet all eventualities.

In this connection, I would bring to his notice two or three matters which though small have become very important. The borders in the east and the borders of Rajasthan are inhabited, as my hon. friend, Dr. Singhvi said, by persons with extra-territorial loyalty. In times of difficulty, they become a source of very great danger. Therefore, steps have got to be taken to see that our borders are properly defended and persons of doubtful loyalty not allowed to create any kind of mischief. This situation obtains both in the east and on the Rajasthan border. I had recently been to the east and spent about 5-6 days there. I was amazed to find that the border over a number of miles is inhabited by persons who have migrated from East Pakistan to Assam or West Bengal. Therefore, it is absolutely necessary that we make all possible preparations to see that no trouble can possibly be created by these elements in those areas.

In any case, so far as the preparations in Pakistan are concerned, the Defence Minister knows about them. Therefore, we have to take all possible steps to see that our Army is not in any way ill-equipped or equipped in a manner not to be able to meet the most sophisticated instruments possessed by the enemy who wants to set foot on our soil. I have no doubt that if proper steps are taken, we will be able to arm our defence forces with up-to-date instruments so that on account of any defect or deficiency or weakness in their instruments our brave soldiers may not suffer any humiliation. This very important problem must be looked into.

[Shri Simatsingka]

Another factor that must be kept in view is the deficiency in transport. During the last conflict with Pakistan, a large fleet of lorries and buses of private owners had to be requisitioned. I am told more than 5,000—6,000 trucks were requisitioned and but for the requisitioning of these trucks and passenger buses, it would have been impossible to the Army to move to the positions—they had to be moved. Therefore, I feel that adequate arrangements should be made for transporting soldiers and other army personnel in times of need from one place to another. For this our fleet of transport vehicles should be increased as much as possible and as quickly as possible so that we may not have to fall back on private transport; private transport should be requisitioned only by way of additional reserves to be used in case of necessity.

Then again, the training that is being given to our NCC should be improved, and I feel that it should be made compulsory in all our colleges. It is compulsory at present also, but a large number of boys are allowed exemption on the merest asking; that should not be permitted and the training should also be intensified, and the training should be such that they may be used at least as a second line of defence, and they may also be used to boost the morale at every place where there is necessity.

Therefore, I feel that the Defence Minister should take all possible steps to see that our armed personnel are equipped with the most up-to-date fighting instruments, that NCC training should be intensified, and that proper steps should be taken in the border areas to see that the borders are properly defended and that we have no cause of being sorry for having neglected them or allowing persons of extra-territorial loyalty to be a danger to our defence.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) :
मभापान महोदय अब यहां से डिफेंस

मिनिस्टर तो चले गये, सवाल तो डिफेंस मिनिस्टर के सामने का था, वह यहां हैं नहीं

Shri K. C. Sharma (Sardhana): Very stout young Minister is here.

Shri U. M. Trivedi: Yes, very stout young Minister is there.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह हमारे देश की खूबी की बात है कि हम अभी तक यह तय नहीं कर पाये हैं कि कौन हमारे दोस्त हैं और कौन हमारे दुश्मन हैं। मेरे दाहिने हाथ को बैठे हुए जो अपने को वामपंथी कहलाते हैं, वे कहते हैं कि आपको जर्मनी से दोस्ती नहीं करनी, अमरीका से दोस्ती नहीं करनी, यू० के० से दोस्ती नहीं करनी और दूसरी तरफ वाले कहते हैं कि रूस से दोस्ती नहीं करनी, चीन से दोस्ती करनी है, और चीन के दोस्त पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है, तो फिर हमारे दोस्त हैं कौन ? कनेडा हमारा दोस्त है तो वह भी अपना माल दूसरों के जरिये वहां पहुंचा देता है, ईरान से हम लोग डरते हैं, अरब वर्ल्ड से हम लोग डरते हैं, सब से हम डरते हैं। हम कभी अपने घर में बैठ कर नहीं सोचते कि हम चालीस करोड़ से ज्यादा हैं और हमारे सामने वे सारे के सारे मिल जायें तो भी 18 करोड़ नहीं हो पाते, तो इन 18 करोड़ से हम क्यों डरने लगे हैं—यह बात मेरी समझ में नहीं आती है, वह डर क्यों? जिन से दोस्ती करनी है, उन से दोस्ती कर नहीं पाते, जिन से डरते हैं, वे हमारे दोस्त बनते नहीं और हमें ज्यादा डराने की कोशिश करते हैं।

मैं सन् ३१ की एक किताब पढ़ रहा था, उस में जापान के एक एडमिरल ने लिखा था—

Must Japan fight Britain?

उसने लिखा कि कहां जापान की लड़ाई अंग्रेजों के साथ होगी, उस लड़ाई में अंग्रेजों को कई जगह शिकस्त देंगे - पर्ल हार्बर में

होगी, होनोलूनु में हुई थी, उसका भी जिक्र था, लेकिन अन्त में उसने लिखा था—

“With all the battles that we will win, we will lose the war because we are not able to surpass the diplomacy of the British.”

वही की वही हालत आज हमारी हो रही है। पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई में उतरे, पाकिस्तान को हम ने शिकस्त दी, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं बना रहा, पाकिस्तान उसी भाषा में आज भी बात कर रहा है। पाकिस्तान का एक भी कदम ऐसा नहीं है जो हमारे साथ दोस्ती का हो, और हम अपने अखबारों में पढ़ते हैं कि हमारे लीडर लोग बोलते हैं कि हम पिण्डी-पीकिंग के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। न पिण्डी तुम को पूछता है और न पीकिंग पूछता है। पीकिंग वाले हमारे से थू-थू करते हैं। कोई भी हमारी परवाह नहीं करता, लेकिन पिण्डी-पीकिंग की ही रट लगाये हुए हैं, पहले हमने चीनी-हिन्दी भाई भाई का राग अलापा और फिर लात खाई, वैसी की वैसी बात आज हो रही है। हम अभी तक इस पिण्डी-पीकिंग मसले पर गाते चले जा रहे हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ, हमारी सरकार जरा इस पर गौर करे, क्या पिण्डी-पीकिंग से डर कर हम अपनी नीति का निर्णय करेंगे या हम अपनी ताकत से अपनी नीति का निर्णय करेंगे। कई आदमी बकवास करते करते कह देते हैं कि दे दो काश्मीर को, अभी एक ने पहले कह दिया कि दे दो काश्मीर को—किस को दे दो, क्यों दे दो, किसका काश्मीर है। हमने जो वटवारा किया हिन्दुस्तान का, जिस राजे-महाराजे ने हिन्दुस्तान की तरफ दस्तखत किए वह हमारे साथ मिला, जिस ने उधर किये वह उधर मिला, वहां के महाराज ने हमारे साथ दस्तखत किये और हम से मिल गया। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी बात क्यों की जाती है और मुझे दुख

के साथ कहना पड़ता है कि हम अपनी तैयारी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम सन् 1965 में जब यह हालत पैदा हुई थी तब शास्त्री जी ने अपोजीशन के लोगों को बुला कर खुल कर बातें बताई थीं, कि पाकिस्तान आज हमारे साथ क्या करने जा रहा है। आज तो सिर्फ हम अखबारों में पढ़ते हैं जो कि हमारे मिनिस्टर साहब डिफेंस कान्सिल में या दूसरी कान्सिल में बोल देते हैं कि ऐसी स्थिति है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान सेवर-जेट ले आया है, इससे ज्यादा हम को कुछ नहीं बताया जाता। हम से इस हाउस में इन बातों को छिपाया जा रहा है।

हम देख रहे हैं कि राजस्थान वार्डर पर आप जाइये, पाकिस्तान की तरफ से वहां इतनी तैयारी हो रही है कि आये दिन लोग यही कहते हैं कि कल हमला होगा, आज हमला होगा, लेकिन यहां पर शान्ति से बंठे हुए हम इन बातों को सुनते चले जा रहे हैं, आखिर हम ने क्या तैयारी की है ?

अभी हमारे वृजराज सिंह जी कुछ कहने लगे कि छोटे-छोटे आदमियों को इनाम नहीं मिला, बड़ों-बड़ों को मिल गया, कुछ छोटे-बड़ों की कदर तो हो गई, लेकिन मैं अभी ईशापुर शेल फॅक्टरी के इन्स्पेक्शन पर गया था। वहां देखा कि वहां पर 9029 आदमी काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से वहां पर सन् 1962 से पहले—उसका नाम तो था राइफल फॅक्टरी, लेकिन राइफल बन नहीं रही थी, सब बन्द हो गया था, हज्जाम जिस से वॉल काटता है, वह मशीन बन रही थी, उस मशीन को बन्द कर के वहां पर राइफल बनाना शुरू किया गया और हमारी राइफल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन लड़कों ने जी-जान से रात-दिन काम किया और इतना काम किया कि जहां पर एक भी राइफल नहीं बनती थी, वहां पांच हजार राइफलें एक महीने में निकलनी

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

शुरू हो गई। उन्होंने अपने काम के सम्बन्ध में कभी ओवरटाइम नहीं मांगा, हालांकि उनको दिया गया और इतनी मेहनत से काम किया कि वहां पर पांच हजार तक राइफलों बननी शुरू हो गई। लेकिन उन में से किसी आदमी को कोई इनाम नहीं दिया गया। उनकी कोई तारीफ़ कहीं पर नहीं की गई, उनको कोई तमगा नहीं दिया गया उनकी बहादुरी का कोई बखान नहीं किया गया, अगर बखान करना है तो ऐसे शूरो का बखान करना चाहिए।

जहां कहा जाता है कि बंगाल की तो सब लेबर कम्यूनिस्ट हो गई है, मुझे उनके लगन और उराल को देख कर ताज्जुब हुआ। अगर सच पूछा जाये तो बंगाल के लीडर्स अपने लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते, वना वहां कोई कम्यूनिस्ट-कम्यूनिस्ट नहीं है। उन लोगों ने वहां खूब काम किया, लेकिन उन के काम की कदर नहीं हो पाई क्योंकि वे फैक्टरी में बैठे हुए काम करते रहे। आज हमारे यहां शेल फैक्टरीयों बढ़िया से बढ़िया शेल बना रही हैं, लेकिन उसका बखान हम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे पास सब-मैरीन्ज नहीं हैं, प्राये क्या लड़ाई होगी और क्या उसके नतीजे होंगे, यह मैं जानता हूँ, लेकिन जनता के दिल में एक उभार है, जोश है, इस जोश को प्राप्त करने की ताकत हमारे अन्दर नहीं है, हमारी सरकार हाथ पर हाथ दिये हुए बंठी है, वह यह सोच रही है कि भाई—हम तो नान-वायलेंट हैं, गांधी जी से नान-वायलेंट सीखा है, इसलिए हम नान-वायलेंट रहेंगे, लेकिन गांधी जी का नान-वायलेंट एक मर्द का नान-वायलेंट था, नामर्द का नान-वायलेंट नहीं था। गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि मैं कमजोर की नान-वायलेंट को पसन्द नहीं करता। अगर वायलेंट हजार गुनी हो तो भी मैं उस को बर्दाश्त करूंगा लेकिन कायर की नान-वायलेंट को

बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आज हम नान-वायलेंट की बात करते चले जाते हैं। आज हम बुद्धिमान हैं, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास प्रेरणा है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी हम ऐटमिक वेपन नहीं बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो क्या हमारे देश को इस से कभी कोई फायदा हो सकता है। अगर बनाते हैं तो इस से हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। हम ने महाभारत के युद्ध तक में देखा कि एक तरफ से एक अस्त्र उपयोग में लाया जाता था, दूसरी तरफ से उस से भी तीव्र हथियार उपयोग में लाया जाता था, फिर दूसरी तरफ से उस से भी तीव्र हथियार उपयोग में लाया जाता था। अगर तीव्र हथियार आप के पास नहीं है जिन के आधार पर हम शत्रु को रोक सकें और हमारे यहां बराबर उस की अपेक्षा बनी रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि एक दिन ऐसा आयेगा, जब हम को दुनिया कोश्ली रहेगी कि हमें रूते हुए हम ने आख नहीं खोली और देश को बरबाद कर दिया।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव रखी गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है।

Mr. Chairman: This discussion will continue on some other day. He may continue his speech on that day.

14.32 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
NINETY-FOURTH REPORT

Shri A. S. Alva (Bangalore): I move:

"That this House agrees with the Ninety-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 24th August, 1966."

Shri S. C. Samanta (Tamluk): Madam Chairman, do you know that my Bill which is of the utmost im-